

Title: Further discussion on the motion of thanks on President's Address moved by Shri Inderjit Singh Rao and seconded by Kumari Meenakshi Natarajan and the amendments there to moved on 3<sup>rd</sup> March, 2010. (Amendments negatived and discussion concluded).

MADAM SPEAKER: The House will now take up item no. 12. Dr. Murli Manohar Joshi will be the last Member to speak on this discussion.

If any hon. Member wants to lay his or her written speech he can do so at the Table of the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): After this item gets over, because today is Friday, instead of taking up the 'Zero Hour' at the end of the day, you may take up the 'Zero Hour' before taking up Private Members' Business.

MADAM SPEAKER: Okay, we will take up the 'Zero Hour' after lunch.

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी):** अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो कुछ चर्चा हुई, उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना। उनके भाषण को भी बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, जिनकी विस्तारपूर्वक चर्चा बहुत से विषयों पर हो चुकी है और शायद बहुतों पर बजट के समय की जा सकेगी। लेकिन कुछ खास बातें जो उन्होंने अपने कई अभिभाषणों में कही हैं, उसमें से एक जो उन्होंने जून, 2009 के भाषण में भी कही थी, वह यह है कि मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया करायेंगा, जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आवास हो। अभी दोबारा भी उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है और कहा है कि --

"In the longer term our food security can be ensured only through sustained efforts. My Government is committed to bring in legislation to ensure food security. "

It has also been said:

"My Government continues to accord highest importance to ensuring relief to the *aam aadmi* on food prices. "

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में 'कौटिल्य' का उदाहरण देते हुए कहा कि

"इस प्रकार, एक बुद्धिमान महा समाहर्ता राजस्व संग्रहण का कार्य इस प्रकार करेगा कि उत्पादन और उपभोग अनिष्ट रूप से प्रभावित न हों। लोक सम्पन्नता, प्रचुर कृषि उत्पादकता और अन्य बातों के साथ वाणिज्यिक समृद्धि पर वित्तीय सम्पन्नता निर्भर करती है।" इसका अर्थ यह है कि पिछले और उससे पहले के बजट में भी इसी प्रकार की बातें कही गयी हैं। खाद्य सुरक्षा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का सारांश है, जिसे मैंने आपके सामने रखा। खाद्यान्नों के मूल्यों पर भी नियंत्रण रखने की बात कही जा रही है और ये घोषणाएं की जा रही हैं कि ये बहुत जल्दी नियंत्रित हो जायेंगी। लेकिन आज भी समाचार-पत्रों में है कि 18 प्रतिशत की दर से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं, जो आपको संकेत दे रहे हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बराबर कह रहे हैं, उनका अनुपालन, मैं समझता हूं कि यह सरकार करने में असमर्थ रही है। अब जरा देखें कि खाद्य सुरक्षा की जो बात कही जा रही है, इसके निहितार्थ क्या हैं? बहुत पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक वाक्य कहा था कि "Everything can wait but not agriculture." सब चीजें रुक सकती हैं, लेकिन कृषि नहीं रुक सकती। मुझे देखकर अफसोस हुआ कि आजकल हमारी सरकार की तरफ से अमेरिका के साथ हमारी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जो बातें हो रही हैं, तो वहां का क्या रूख है? Mr. Earl Butz, the former Agriculture Secretary of USA had made a statement. In that he said: "Food is a weapon. It is now one of the principal tools in our negotiating kit." वह अनाज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जिन देशों में अनाज कम होता है, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक चीजें हैं यानी खाद्य के मामले में हमें पूरे तौर पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है।

लेकिन हो क्या रहा है? मैंने इस मामले में कुछ बजट प्रावधानों को देखा, मैं ज्यादा की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। यह कहा जाता है कि कृषि के लिए हमें बहुत कुछ करना है और किसानों के लिए हमने इतना दे दिया है, किसानों के लिए हम यह कर रहे हैं, लेकिन जरा उसकी गहराई में जाइए, जो किसानों को ऋण और सहायता देने की नीति है, जरा उसके पेंच को समझिए। There is a four-pronged strategy for agriculture. The first of these are: agricultural production. It could mean anything for anybody. The other three are: gold mine for large corporations, but not for the farmers. जो कुछ और किया जा रहा है, बड़े पूंजीपति, बड़े उद्योगपति के लिए है, छोटे किसानों के लिए नहीं है। आप देखें कि एक नीति बनाई गयी है, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फ़ीड्सूभ और यह कहा गया है कि इसमें हम उन सारी चीजों के लिए ऋण देंगे, जो इस वेस्टेज को रोकेंगे यानि कोल्ड स्टोरेज बनाएं या दूसरे इस तरह के कार्य करेंगे। इसमें कहा गया है कि 25 करोड़ रूपए तक एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। 25 करोड़ रूपए ऋण लेने वाले कितने किसान हैं, यह मैं कृषि मंत्री जी से पूछूंगा और वित्त मंत्री जी से भी कटूंगा कि जरा इसका हिसाब दें कि 25 करोड़ रूपए के ऋण कितने किसानों के लिए है जो वास्तविक खेती करते हैं? छोटे किसान को 25,000 रूपए लेना मुश्किल है, लेकिन 25 करोड़ रूपए किसको मिल रहे हैं? एग्रीकल्चरल लोन के नाम पर किसी भी उद्योगपति को मिल सकते हैं जो यह कहेगा कि मैं कोल्ड स्टोरेज बना रहा हूं, जो कहेगा कि मैं एक रेफ्रिजरेटेड यातायात बना रहा हूं। उस कंपनी को ये 25 करोड़ रूपए मिल जाएंगे और यह एग्रीकल्चरल लोन उन टर्म्स पर मिलेंगे, जो किसान के नाम पर मिल रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** किसान को 10,000 रुपए कर्ज लेने पर 2,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।... (व्यवधान)

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी) :** हाँ, वहां ऋण लेना पड़ता है और यहां अगर 25 करोड़ रुपए लीजिए तो शायद इसके लिए कमीशन भी दिया जाएगा कि आप 25 करोड़ रुपए ले लीजिए। यह कैसी खाद्य सुरक्षा की बात है? यह किस किसान के लिए आप बात कर रहे हैं? आप आगे देखिए, इसमें कहा गया कि किसान बाहर से भी खेती के लिए ऋण ला सकते हैं, कौन लाएगा? केवल बड़े कारपोरेशन लाएंगे, छोटा किसान तो नहीं ला सकता है। यह कौना से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, खाद्य सुरक्षा को ठीक रखने के लिए आपने नीतियां बनाई हैं? किसानों को जो कर्ज दिए गए हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के रूप में, जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, 25 करोड़ रुपए तक हैं या 25 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, वे किसके पास हैं? उनकी एक सूची इस सदन के सामने आ जाए तो पता लग सकेगा। इसमें एक और तमाशा हुआ है कि सालों में 25,000 रुपए ऋण लेने वाले किसानों की तादाद घटी है और 10 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने वाले एग्रीकल्चरल लोनर्स की तादाद बढ़ी है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि किस तरह इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और इससे किस प्रकार से आप खेती को आगे ले जा सकेंगे।

आप बार-बार यह कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। यह पैसा आपने एक बार दिया, लेकिन आप बड़े कारपोरेशन को कितना माफ करते हैं? अगर आप देखें, कभी 80,000 करोड़ रुपए, कभी 70,000 करोड़ रुपए, कभी 60,000 करोड़ रुपए हर साल दिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी सदन को यह अवगत कराएं कि पिछले पांच सालों में हर वर्ष कितने ऐसे बड़े कारपोरेशन को लोन माफ किए गए हैं या रितीफ दिया गया है, चाहे वह टैक्स के द्वारा हो, एक्साइज के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से दिया गया हो। अगर आप वह 60,000 या 70,000 करोड़ रुपए हर साल उनको दे रहे हैं और एक बार आपने किसान को 70,000 करोड़ रुपए दे दिए, वह भी किसान को नहीं, किसान के नाम पर बैंकों को दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि उससे आप किसान का कोई भला कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कैसे इस काम को कर रहे हैं? अभी भी हालत यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अभी दो-चार दिन पहले उड़ीसा में 50 हंगर किल्स किसानों ने किए हैं, लेकिन पिछले सालों के जो आंकड़े हैं, करीब-करीब 1.5 लाख किसानों ने पिछले सालों में आत्महत्या की है। हर साल किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है, अभी भी इसमें कमी नहीं आई है। 15,000-16,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। यह क्या स्थिति है? किसी-किसी राज्य में तीन हजार-चार हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे अधिक अफसोस की बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी के राज्य में भी ऐसा हो रहा है। वहां भी कमी नहीं आई है, जैसे देश में कमी आई है, उसी हिसाब से कमी आई है, लेकिन आत्महत्याएं रुकी नहीं हैं। इसलिए किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं, नहीं रुक रहीं, हंगर डैट्स नहीं रुक रही हैं, लोगों का मैन्यूटीशियन नहीं रुक रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के पटल पर कुपोषण दूर करने में अभी बहुत पीछे हैं, हमने उसे पूरा नहीं किया है। तो आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप देश की इस खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करना चाहते हैं? हमें बताया गया कि कानून बनाना चाहते हैं। मैं आज कृषि पर बात नहीं कर रहा, वरना मैं आपको बता सकता था कि उत्पादकता के मामले में भी आप क्या कर रहे हैं। आप उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जिन देशों के साथ आप समझौता कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। वह उत्पादकता बढ़ाने का सवाल नहीं है, वह एग्रीकल्चर को को एग्री बिजनेस में बदलते हैं, उनकी रूचि आपके देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में नहीं है। आपकी मार्केट्स को लेने में उनकी रूचि है। आपके बीज के व्यापार को लेने में उनकी रूचि है। आपके यहां अपने पेस्टीसाइड्स फेंकने में उनकी रूचि है। आपके यहां उत्पादकता बढ़ाने में उनकी रूचि नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास सरप्लस फूड है। आपके यहां अगर अनाज कम होगा, आप उनके वहां से इम्पोर्ट कर लेंगे। इसलिए उस नीति पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए कि इस तरह से कैसे आप देश की खाद्य सुरक्षा करेंगे। कहते हैं कि हम कानून बनाकर करेंगे। मुझे कभी-कभी हंसी आती है कि सरकार के लोग शायद यह समझते हैं कि मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में अगर अच्छे पैकेट्स में रखा हुआ विदेशी अनाज है तो खाद्य सुरक्षा हो गई और उत्पादकता बढ़ गई। अनाज की उत्पादकता मॉल्स में नहीं बढ़ती है, दुकानों में नहीं बढ़ती है, अनाज की उत्पादकता खेतों में बढ़ती है, खलिहानों में बढ़ती है और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसानों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे हैरत होती है कि वह बार-बार कह रही हैं, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है। आप उस तरफ कुछ ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आपकी नीति किसान फोकस नहीं होगी, तब तक न तो आपके देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, न आपको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में मदद मिलेगी, आप इस देश का विकास नहीं कर सकेंगे। भूखे पेट का हिन्दुस्तान किसी रास्ते पर नहीं चलेगा। इसलिए पहली जरूरत है हिन्दुस्तान को हंगर फ्री बनाएं, भूख मुक्त हिन्दुस्तान बनाएं, ज़ीरो हंगर की पॉलिसी बनाएं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक आप ज़ीरो हंगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक हिन्दुस्तान आग नहीं बहेगा।

आप कहते हैं कि हम कानून बना रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती, अगर इस कानून से आप ज़ीरो हंगर ले आते। लेकिन पहले यह देखें कि इस देश में भूखे कितने हैं। इसी पर आपके यहां एकमत नहीं है। आप बिलो पावर्टी लाइन की सीमा को निश्चित नहीं कर पाए हैं। कोई सरकार नहीं कर पाई, हमने भी कुछ किया था, आप भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह ग्राउंड रिएलिटी से बहुत दूर है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपने एक कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है।

"Expert Group to advise the Ministry of Rural Development in the Methodology for conducting the Below Poverty Line Census for the Eleventh Five Year Plan "

इस रिपोर्ट को आप गहराई से पढ़ें और देखें। मैं नहीं समझता आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह एक बिल्कुल जमीनी स्थिति को हमारे सामने रखती है। इसलिए इसे गहराई से समझें और इसमें राजनीति न करें। हमने 28 प्रतिशत किया और आपने 27 प्रतिशत किया, यह बराब मेहरबानी मत करिए। यह देखें कि जमीन पर कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कौन गरीब हैं, कौन दरिद्र हैं। खाली गरीब ही नहीं, दरिद्र कौन हैं। कौन ऐसा है जो दो जून खाना तो क्या, एक जून भी खाना प्राप्त नहीं कर सकता है। वह गरीबी की सीमा के नीचे बहुत दूर तक नीचे है। इन सारी चीजों को आप देखें तो यह कमेटी कहती है,

"Food security is need for all – and not only for those who are officially Below the Poverty Line।"

भोजन की सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, फिर वे यह कहते हैं

"This issue is particularly relevant for combating food-related hunger because as we will argue later in this Section, the number of food deficit people has at least doubled the number of officially declared people in India, thus there is every case for enlarging the category of those entitled to cheaper food from the Government."

उन्होंने यह संख्या 50 प्रतिशत तय की है कि कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इसी कमेटी के कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह 50 प्रतिशत क्यों, अगर सही आंकड़े लाए जाते हैं तो सारी स्थिति को देखकर शायद यह संख्या 70-75 प्रतिशत तक जाएगी, 50 प्रतिशत पर ही क्यों। मैंने जब इसे देखा है, इसमें एक भावना उनके दिमाग में भी काम कर रही थी कि सरकार के लिए ज्यादा कठिनाइयां पैदा न हों। यह केवल सरकार का सवाल नहीं है, सारे देश का सवाल है। आपके लिए हो या हमारे लिए हो, अगर इस देश के अंदर 80 प्रतिशत गरीब हैं तो इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो 80 प्रतिशत के लिए इंतजाम करने के वास्ते सरकार के सामने आने न आए। वह चाहे बिहार में हमारी एनडीए सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश या गुजरात में बीजेपी की सरकार हो या पंजाब में हमारी सरकार हो। अगर 80 परसेंट लोगों के लिए इंतजाम करना है तो करना है। इस देश के किसी भी आदमी को भूखा नहीं रहने देना है और इसके लिए हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप इसका रास्ता अमरीका के साथ समझौता करके निकालना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और जिनेटिकली मोडिफाइड फूड देकर करना चाहते हैं तो उस पर बहस होगी और देश में तीव्र मतभेद होगा।

आप देश की कृषि-व्यवस्था को देखिये। कालाहांडी के बारे में कहा जाता है कि वह भूखग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि कालाहांडी से हजारों टन धान संग्रहीत भी होता है और वहां सबसे ज्यादा भूख भी होती है।

**मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):** आप माननीय आडवाणी जी को समझाइये।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** जी, वह तो अलग बात है, पहले आपको समझा लूं फिर उनको समझा लूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** आप चैयर को एड्रेस करें।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** मेरा कहना यह है कि आप इस रिपोर्ट को गहराई से देखें। एक दूसरी रिपोर्ट हमारे माननीय तेंदुलकर साहब की है। उन्होंने आपको कुछ मापदंड दिये हैं। आप उन्हें जरा जमीन के साथ जोड़िये, कीमतों के साथ जोड़िये, लोगों की बढ़ाती के साथ जोड़िये और आप मेहरबानी करके सबसे पहले गरीबी की परिभाषा ठीक कीजिए। आज हालत यह है कि दुनिया के बहुत से देशों में अनाज की समस्या है, खाने की समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए लोगों ने क्या किया? ब्राजील में, वर्ष 2003 में, वहां के प्रेसीडेंट ने कहा कि हम हरेक आदमी को दिन में तीन बार खाना खिलाएं और चार करोड़ साठ लाख आदमियों को उन्होंने खाना खिलाया और उसके लिए 12 मिलियन डालर वर्ष 2005 में खर्च किये। फिर इजीप्ट ने अपने यहां यह काम किया और दो मिलियन यूएस डालर अपने यहां खाना खिलाने पर खर्च किये। फिर मैक्सिको ने यह काम किया। उनका ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 1997 में शुरू हुआ और 40 लाख घरों को एक मिलियन यूएस डालर खर्च करके खाना खिला रहे हैं। इसी तरह से अमरीका में भी 31.6 मिलियन आदमी यानी दस में से एक आदमी फूड स्टैम्प प्रोग्राम से लाभान्वित होता है। अगर अमरीका की यह हालत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फूड सरप्लस देश है तो हमारी क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप किधर जा रहे हैं? आप इस देश को भूखों का, बीमारों का, अशिक्षितों का देश क्यों बनाते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पिछले साल ही, डेढ़ करोड़ आदमी इस देश के अंदर गरीबी की सीमा रेखा में चला गया है। हर साल अगर गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो किस आधार पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि हम आने वाले समय में, इस देश को विश्व की महानतम समिति में खड़ा करेंगे। आप वर्ष 2015 तक भूख को आधा करने के लिए कमिटेड हैं। लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि आप वर्ष 2015 तक, इस देश में भूख को आधा कर पाएंगे। मुझे खुशी होगी अगर यह काम किया जाता है और उसके लिए कोई रोड-मैप होगा तो सारा सदन आपकी सहायता करेगा, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आता है। कभी इस पर चर्चा होगी तो हम आपको रास्ता बता सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, मगर अमरीका से जो आप समझौता कर रहे हैं, जिसे आपकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसे आपने सदन के सामने नहीं रखा है, भगवान के वास्ते उसका पुनःरीक्षण करें और हिंदुस्तान के किसान को अमरीका का पिछलान्नू न बनाएं। हम 8000 साल से इस देश में खेती कर रहे हैं, वे 300 साल से खेती करना जानते हैं। हमारी जैव-विविधता को आप नष्ट होने से बचाएं। हमारी धान की हजारों जातियां खत्म हो चुकी हैं, हमारे फूल-पते, जड़ी-बूटियां खत्म हो रही हैं। आप भगवान के वास्ते किसान को, आम आदमी को साथ लें, ये अमरीकन वैज्ञानिक हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, विज्ञान को थोड़ा-बहुत समझता हूं और जितना मैं अमरीकन्स को समझता हूं, उनकी दुरनीति को समझता हूं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से महामहिम महोदय को चेतावनी दे रहा हूं कि इस देश की खेती अगर आपने अमरीका का गुलाम किया, तो आप इस देश की आजादी को नहीं बचा सकेंगे।

आप पता नहीं इस देश को कहां ले जाएंगे? यह देश भूखे नंगों का देश बन जाएगा, इसके लिए मुझे स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी से कहना पड़ता है कि आज आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे अफसोस होगा कि किसी दिन आप सोएंगे कि आपकी नीतियों ने देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इस देश को इसके लिए रोना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि इस देश की खेती को, इसकी परम्परा को स्वाधीन रहने दीजिए। इस देश के किसानों को काम करने दीजिए, इसे अमरीका के हाथ में गिरवी मत रखिए।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बारे में कही है। खाने के बाद अगर कोई चीज जरूरी है, तो वह सुरक्षा है। बहुत समय से संसद में डिफेंस के बारे में चर्चा नहीं हो पाई है। आप कभी चर्चा कराइए कि देश में सुरक्षा के क्या हालात हैं। आज भी हमने अखबार में पढ़ा है कि कश्मीर में घुसपैठ हुई है। हमारे गृहमंत्री जी कहते हैं कि सिविलोरेट में ढील हुई है, गिरावट आई है। यह क्या बात है? देश का व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस क्यों कर रहा है? बाहर से जो आक्रमण होने की संभावना रहती है, उसके लिए हम क्या करें? हम जैसे खेती को अमरीका के साथ जोड़ रहे हैं, वैसे ही हम समझते हैं कि समय आने पर वह शायद अपना न्यूक्लियर टिगर हमारे लिए छोड़ देगा और हमें बचा लेगा। आपकी प्रतिरक्षा की जो सामग्री बन रही है, वह बहुत विचित्र है। वह केवल पाकिस्तान ओरिएंटेड है, लेकिन खतरे दूसरी तरफ से भी हैं। इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। भारत सिकुड़ रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** तिब्बत हमारा बार्डर था, उसे आज आपने हिमालय के फुटहिल्स में ला दिया है। नेपाल जो कभी हमारा एक प्रमुख समर्थक होता था, उसे आपने अखड़ा बना दिया है। एक तरफ से चीन पाकिस्तान के माध्यम से गोडार तक पहुंचा हुआ है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा हुआ है, सारे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आज चीन की गोद में जा रहे हैं। चीन आज सारे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाता जा रहा है। आपकी सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अभी चीन से बहुत पीछे है। जो स्थितियां हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। हम किस आधार पर विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं? हम तो आज के समय में क्षेत्रीय शक्ति भी नहीं हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जहां हम थे, उससे बहुत पीछे हम चले गए हैं। 1947, 48, 49 में हमारी जो स्थितियां थीं, वे आज बहुत पीछे छूट

गई हैं।

**अध्यक्ष महोदया :** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** महोदया, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, लेकिन आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** चीन ने हिंदुस्तान को बीस-तीस टुकड़ों में बांटने की कोशिशें की हैं। सारे हथियार उसने इस तरह से समायोजित किए हैं। अरुणाचल के ऊपर वह अपना कब्जा बनाना चाहता है। सिक्किम में वह मांग कर रहा है। अवसाइ चीन वह कब्जे में लिए बैठा है। अब जब अवसाइ चीन की बात आती है, तो कश्मीर भी मुझे याद आता है। श्रीमान आडवाणी जी ने इस सवाल को उठाया था। मैं चाहता हूं कि वह सवाल सही परिप्रेक्ष्य में सदन के सामने बना रहे। सदन का प्रस्ताव था कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में सदन को आश्वस्त करें। श्रीमान आडवाणी जी ने यही सवाल उठाया था। अगर आप इस मामले को दोहराकर कहते हैं...(व्यवधान) सिर्फ यही नहीं, कृपया करके आप मेरी बात सुनिए। इन्हीं बातों से संदेह पैदा होता है कि आप कश्मीर मामले में कुछ ढील कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदया :** माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** आप इस मामले में बेबाक हो कर कहिए। फारूख साहब बैठे हुए हैं। यह प्रस्ताव इसी सदन में पास हुआ था।...(व्यवधान) हम हैं, हम तो कह ही रहे हैं। हम तो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसे दोबारा दोहराएं। प्रधानमंत्री दोबारा प्रस्ताव रखें और हम उसका समर्थन करेंगे।...(व्यवधान) हाँ, हमारे शरद पंवार उसे दोहराएं। हम उसे दोहराना चाहते हैं। देश को आश्वस्त करना चाहते हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाएं। आप क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं।

माननीय सदस्य आप भी बैठ जाएं। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

â€¦(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** माननीय सदस्य के भाषण क अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) â€¦\**

**अध्यक्ष महोदया :** मुरली मनोहर जोशी जी, अब आप अपनी बात जल्दी से समाप्त कर दीजिए। It is time to conclude.

...*(Interruptions)*

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** महोदया, मैं दो और बातें कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** ताल सिंह जी, आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** अगर टोकाटाकी नहीं होगी तो जल्दी बात समाप्त हो जाएगी।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप जल्दी समाप्त कीजिए। तुरंत समाप्त कीजिए। I will give you one minute to speak.

...*(Interruptions)*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): I would like to respond to Joshi ji. I would like to inform him हिंदुस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं।...(व्यवधान)

**डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** मैं यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Dr. Farooq Abdullah, please address the Chair.

...*(Interruptions)*

**डॉ. फारूख अब्दुल्ला :** माननीय प्रधानमंत्री कहें या न कहें। ...(व्यवधान) आप सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे याद आता है कि आपके ही लीडर वाजपेयी जी ने भी यही कहा था - कभी यह मत समझिए कि देश इतना कमजोर है कि कोई भी हमें खा सकता है, चाहे वह अमरीका हो, चीन हो या कोई और मुल्क हो। चीन कुछ भी कर ले, हिन्दुस्तान का भूखा भी कुल्हाड़ी उठाकर मुल्क की सेवा के लिए निकल पड़ेगा।...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** चीन आपकी सीमा में प्रवेश कर चुका है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please take your seat. Mulayam Singh ji, please take your seat.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुरली मनोहर जोशी जी, अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं दो बातें कहूंगा। एक बात तो यह है कि मैंने प्रस्तावक महोदय का भाषण सुना। इसमें लगभग कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई टिप्पणी की जाए। लेकिन एक वाक्य ऐसा था जो उन्होंने लालू प्रसाद जी को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे हिंदी में बात करेंगे जब आप और हम वृंदावन में गाय चराने जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। इसके दो पक्ष हैं - वे वृंदावन में गाय चराने तो तब जाएंगे जब गाय इस देश में बचेगी। जिस रफ्तार से गायों का वध हो रहा है, मुझे शक है कि उन्हें गाय के बजाय किसी और जानवर को चराने के लिए वहां जाना पड़ेगा। जिस भाषा की बात की है, शायद उस पक्षी का जिक्र किया था, वे केवल उसी की भाषा में उससे बात करते रहेंगे, इस सदन को जो भाषा लगती है। हिंदी सदन की भाषा है। भारत की राजभाषा है, संविधान की भाषा है इसके लिए गाय चराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले अपने दिमाग को चलाइए, ठीक रखिए। आपको हिंदी में बात करनी चाहिए, करनी होगी। आप न करें तो अलग बात है लेकिन आप उसे चरवाहों के साथ जोड़ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : भारतीय भाषाओं में करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप चुप रहिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : भारतीय भाषाओं में करें। मुझे इस बात का फल है कि आपने कहा कि आप चरवाहों से हिंदी में बात करेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बात कीजिए। आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : देश का चरवाहा भी हिंदी बोलता है, अंग्रेजी नहीं बोलता है।...(व्यवधान) आप इस बात का ध्यान रखें कि हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हिंदी के प्रति इस प्रकार के अपमानयुक्त शब्दों का प्रयोग करें। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Joshi ji, address the Chair. Your time is up.

...(Interruptions)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। प्रस्तावक महोदय के बाद समर्थक महोदय ने भाषण किया, मुझे भाषण के बारे में उन्हें बधाई देनी है। उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पहचान का उठाया। उन्होंने पहचान यूनिक आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ी लेकिन वह जरा कुछ हटकी हो गई क्योंकि आप इस देश की पहचान एक नंबर से देना चाहते हैं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। आप इस देश के आदमियों को नंबर बनाना चाहते हैं। यह बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, गांधी का देश है, सूफी-संतों का देश है, राम और कृष्ण का देश है, इसकी पहचान नंबर से नहीं होती। आपकी मेहरबानी होगी, आप इस देश को नंबर में मत बदलिए। उसे इंसान रहने दीजिए, उसकी इंसानियत की पहचान रखिए, उसकी परंपरा की पहचान रखिए, उसकी संस्कृति की पहचान रखिए। आप ध्यान दीजिए और भारत की भारतीयता की पहचान दीजिए लेकिन आप क्या पहचान दे रहे हैं कि आप गरीब हैं। आप गरीबों को इस देश के गरीबों की पहचान दे रहे हैं। ...(व्यवधान) गुरुबत की पहचान देना चाहते हैं। आप क्या देना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप क्यों खड़े हो गए। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम भारत को गौरवशाली पहचान देना चाहते हैं। भारत की पहचान दुनिया में महान संस्कृति और परंपरा के तौर पर रहेगी।...(व्यवधान) वे नंबर नहीं हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Your time is up. अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : नंबर में बदलने की नीतियों को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ...(व्यवधान) मेहरबानी से देश को सही पहचान देने का काम करें। भगवान आपको ऐसी शक्ति दे, बुद्धि दे कि आप इस देश को समझें, इसकी सही पहचान को समझें, परंपराओं को समझें, संस्कृति को समझें, इतिहास को समझें। आप तब जाकर इस देश की नीतियां ठीक बना सकेंगे।

**\*श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर):** बजट सत्र अन्य सभी सत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि वह बीते वर्ष में सरकार के कामकाज की समीक्षा के रूप में तो देखा ही जाता है साथ ही उसे आने वाले वर्ष में सरकार के भावी कार्यक्रमों, योजनाओं और कदमों की प्रस्तावना भी माना जाता है।

राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत की सफलता की कहानी तब तक अधूरी है जबतक वंचित तबके के लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता। इस संदर्भ में यूपीए सरकार के निर्णय ऐतिहासिक रहे हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम महानरेगा को देखें जिसने हर इस देश के निवासी परिवार को कानूनन रोजगार की गारंटी दी है। दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार देने की योजना महानरेगा है। रोजगार के साथ स्थायी संपत्ति का निर्माण सरकारी व निजी दोनों इस योजना में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बाड़मेर व निजी दोनों इस योजना में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बाड़मेर जिले में निजी टांके का निर्माण उदाहरण है कि 50000 परिवार एससी/एसटी व बीपीएल जिनको सरकार ने रोजगार के साथ पेयजल के लिए भी सार्थक कदम उठाये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी राष्ट्रपति ने कई नये सार्थक पहलकदमों के संकेत दिए हैं इनमें बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी बनाये जाने और जल्दी ही राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के गठन की बात प्रमुख है।

सरकार 2012 तक हर घर में बिजली का लक्ष्य रखा। इसके लिए राजीवगांधी विद्युतीकरण जैसी योजना जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो चुके हैं। देश में दूसरी हरित क्रांति का भी उल्लेख किया गया है इसके लिए नई तकनीकों को बेहतर बीजों, उन्नत कृषि तरीकों को प्रभावी, जल प्रबंधन तकनीकों और उन अधिक मजबूत ढांचों की आवश्यकता है जो किसानों को वैज्ञानिक समुदाय ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बाजारों से जोड़े।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के बावजूद कारोबारी साल 2009-10 में आर्थिक विकास दर 7.5 फीसदी रही है। जो विश्व में सर्वाधिक है। अगले वित्त वर्ष 2010-11 में इसके 8 फीसदी व 2011-12 में 9 फीसदी तक रखने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह संभव सिर्फ उसकी नीतियों व योजनाओं के कारण ही हो सका।

सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि वैश्वीकरण की नीतियों और जनकल्याण के कार्यक्रम को एक साथ चला सकती है। सुनील खिल्लाणी जैसे राजनीतिशास्त्री या उनके जैसे कई अर्थशास्त्री आज नए भारत के लिए इसी आइडिया की वकालत भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत को उदारीकरण भी करते रहना चाहिए और साथ में गरीबी और पिछड़ेपन का दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं रखनी चाहिए। अगर भारत उदारीकरण के माध्यम से अपनी विकास दर नहीं बढ़ायेगा तो पिछड़ापन दूर करने की योजनाएं चलाने के लिए धन नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के लिए लगभग 4 हजार करोड़ ₹0 से ज्यादा कि जरूरत है आजादी के 62 साल बाद भी हमें मीठा पानी पेयजल के लिए नहीं मिल रहा है। इस तरह की समस्याओं जिसमें ज्यादातर भारतीय तूरत हैं उनका समाधान सर्फ आर्थिक विकास है और वे सिर्फ सोनिया गांधी जी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ही कर सकती है। इसलिए देश की जनता में यूपीए को 2009 के आम चुनाव में जनआदेश दिया है।

**\*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):** I support the motion of Thanks on the President's address. I quite agree with my colleagues in expressing my deep concern that it has been a tradition that whenever the President speaks to both Houses of Parliament, everybody listens in pin-drop silence, but unfortunately over the last two Budget Sessions, we are drifting away from this tradition. No doubt that our country is facing various problems. Be it price rise, Naxalite attacks in some parts of the country, foreign engineered terrorists attacks on our innocent people and severe drought in the country. These problems which will have to be readdressed by active co-operation of all the political parties.

Our government was voted to office with a clear cut mandate to protect and deepen the values of pluralism and secularism and to ensure rapid growth with justice and fairness for all. The biggest achievement of our government was that it has successfully combat with the global economic slowdown by adopting strong policies that our economic growth which had slowed to 6.7% in 2008-2009 has improved around 7.5% in 2009-2010. Developed nations across the world, have faced recession during the year 2009-2010, but India along with China have performed well remarkably during this year of recession.

We have faced with extreme drought situation in some parts of the country and in some other parts of the country, there was flood. Our government, keeping in view of the draught situation and its impact on the farmers has allocated Rs.4,000 crore from the National Calamity Contingency Fund and the Calamity Relief Fund to the drought affected States. Diesel Subsidy Scheme was introduced. Several other measures were taken to minimize loss in production due to drought. Water conservation works in the fields of small and marginal farmers was brought under the Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. I am glad that due to these efforts, we were able to contain fall in food production to a large extent.

There has been pressure on the prices of foodgrains and food products. My government despite a significant increase in the procurement prices of food grains, kept central issue prices of public distribution constant. Import of essential commodities was liberalized. Lakhs of tones of wheat and rice were released in the open market. Additional wheat and rice were released through the various cooperative institutions to benefit the consumers at the retail level.

Appropriate new measures to strengthen the security apparatus of the country to equip it to meet the grave challenge posed by terrorism were taken. Though, infiltration to terrorists from across the line of control in J&K has gone up, but our security personnel were able to achieve significant improvement in J&K.

Our Government has given 8000/- price for sugarcane and paddy which is widely appreciated by one and all. Banks are giving agriculture loan starting from 25,000/- onwards food and essential prices also started decreasing. With this I conclude.

**\*SHRI SAMEER BHUJBAL (NASHIK) :** I support the motion. The President's Address is an important event in the parliamentary calendar. It sets the agenda for the Parliament. It is a vital channel of communication between the Government and the Parliament. It captures the major highlights of the entire gamut of the Government and provides an umbrella framework for debates on any aspect of the Government and provides an umbrella frameworks for debates on any aspect of the Government functioning. Customarily, therefore, the debate on the Motion of Thanks to the President's Address is the first business to be transacted by the House. The sanctity of the debate is somewhat diluted when you find that the Opposition insisted on discussing some other issues before this debate, whereas this particular debate has ample scope for doing so.

My learned colleagues from the Opposition have said in the House and outside it that the President's Address is a sort of advertisement card of the Government. I would like not to contradict it, as this has been the pattern for all Governments including the NDA Government and there is nothing wrong in this pattern. When you highlight your achievements, you derive a sense of satisfaction of the work done; but at the same time you need to be introspective and self critical. And, I am happy that this President's Address, while outlining the efforts and achievements of the Government, has also mentioned about the critical challenge to our nation-building efforts. Through this debate, all sections of the House should endeavour to provide some inputs to the Government to address the challenges.

Speaking at this time of the debate is not very easy, as most points have been touched upon by my learned colleagues. However, I would like to briefly touch upon some major areas of the Address.

Hon'ble President's Address was reassuring in respect of several key areas in the social sector, notably schemes for advancement in rural areas in terms of housing, road connectivity, communication network, as well as setting up of schools and colleges in the backward areas. The growth and development in this broad sphere is critical for the country's future progress.

The Address in paragraph 3 reiterates the commitment of the Government to the cause of the welfare of *aam admi* for achieving the goal of inclusive growth and development. My colleagues from the opposition have said that address gives the impression of glossing over the serious price rise question, which had seriously impacted the common man. There are no

two opinions on the adverse impact of price rise on the quality of life of our people, especially in the rural areas. But, in the context of the President's Address, I would like to mention that the Address has substantively raised this issue in several paragraphs. The efforts taken to control prices of essential commodities have been highlighted and the causes for this which lay in production shortfalls and the increased international prices of these commodities have been delineated. In paragraph 7 of the Address, when the Hon'ble President said that there has been unhappy pressure on the prices of foodgrains and food products, all of us should be reassured that concealment is not the policy of this Government, Transparency is the mantra of our success. The Government is committed to a long term growth of agricultural sector as well as efficient management of food economy for ensuring food security for all our people.

The issue of terrorism also concerns all Indian. After 26/11, the government has taken steps to better organize the internal security apparatus and these find detailed mention in the President's Address. We have a zero tolerance for terrorist activities. However, the Government is concerned at the revisit of terrorist incidents, as evidenced in Pune. Terrorism in India is, to a considerable degree, linked to developments in our neighbourhood, especially in Pakistan. Growing influence to Talibans in Pakistan is a cause for concern. The infiltration level from the Pakistan side has gone up. The Government is appropriately seized of the matter and in different levels of our bilateral engagement, there will be nuanced reference to this factor.

The country's internal security situation, except the left wing extremist activities, has been largely under control. Our very efficient and visionary Home Minister has taken an integrated initiative to address the naxal violence in close coordination with the affected states. Security of life and property is the absolute minimum for growth and prosperity of our country as also its people. Our united efforts will bear fruit. We should not see security from the blinkers of politics. However, absence of two Chief Ministers from the Meeting of Home Minister with the Chief Ministers of naxal affected states in February 2010 at Kolkata is indeed distressing. It indicates that some of the affected states are yet to realise the threat of naxalism to our internal security.

The Address has one very illuminating aspect-the emphasis on education, as a critical factor to accelerated inclusive growth. With this in view, the Government has made significant investment in primary education through Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-day Meal Programme. The Right of Children of Free and Compulsory Education, Act 2009 has been notified. We need to move faster in this direction as universalisation of primary education will play a very important role in addressing the problem of child labour, abuse of child rights and so on.

The biggest relief, I would say, is the strength and resilience of our economy and the economic policies, which could minimize the impact of global economic crisis. The Government deserves our wholehearted compliments. Our economy is growing at 7.5%. The way our economy is growing. I have a feeling that we would touch double digit growth in not too distant future. Having said that, I would like to emphasize that we need to attach top priority to our agriculture to maintain its growth momentum. Scientific innovations on farm inputs and biotechnology must continue through R&D.

At the end, I would like to mention the emphasis given in the Address on extending modern communication facilities in the rural areas. Financial support is provided from the Universal Service Obligation Fund to set-up 10,000 towers in the rural areas. This is a very important step in connecting our rural areas. I represent Nashik in Maharashtra, where the major problem is lack of adequate mobile connectivity. Signal is very poor, towers are not adequate. Madam Speaker, through you, I would like to apprise the concerned Minister to look into this problem. I hope, with this new initiative, the problem of my constituency as also other rural areas would be adequately addressed.

Through you I would like to attract your attention on some of the problems being faced by my constituency Nashik and particularly Maharashtra in general. The phenomenal increase in population of small and medium towns like Nashik largely on account of inward migration has led to severe set-backs in urban development. This has created a number of problems like shortage of dwelling units, mushrooming growth of slums, encroachment of public land etc. The pace of urbanization is creating a number of problems in the process of proper development of many such cities. Therefore, keeping in view this peculiar and gigantic problem the Centre's intervention is urgently sought in implementation of NREGA and JNURM to strengthen the civic infrastructure of the city.

Another area is the 'Youth Development'. While the role and contribution of youth is of vital importance in all countries, it is particularly significant in a country like India where the proportion of the youth in the country's overall social and demographic profile is continuously increasing. According to the 2001 Census, there were approximately 355 million people in the 15 to 35 age group, 74 per cent of whom lived in rural areas. The number was expected to rise to approximately 510 million by 2016. Both central and state governments need to harness the energies of this large group, providing them with adequate infrastructure levels. However, organized effort appears to be forthcoming over a national scale to tap the potential of the Youth. Youth are the foundation for the development of the country and unless emphasis is laid on youth



programme and put the youth on the right track and right direction, the ultimate goal of nation building cannot be achieved.

As Delhi, is going to organise 2010 Commonwealth Games, we should take special efforts to increase sufficient co-ordination among various Sports bodies within the country and enhance our Sports infrastructure throughout the country, among youth and masses.

Another area which I would like to highlight is that to integrate Computer Technology/ICT (Information and Communication Technology) in Teaching Learning process/Class Room Transactions in our schools. Madam, I would only request you that it should be made integral to Sarva Shiksha Abhiyan where there should also be provision to provide CDs, training for block resource persons/teachers and assistance for monitoring and research.

Finally, I would like to see the President's Address as a document which has captured the spirit of good governance. It is articulated through a sense of sensitivity and seriousness of the Government to issues of price rise and security, through a sense of long empowerment of the women, Dalits and Minorities, through a sense of long term vision on infrastructural development and technological modernization, besides the issues concerning climate change and energy security. The Government is conscious of its responsibilities. We need to strengthen its hands. With these words, I thank you Madam Speaker for giving me this opportunity to participate on this motion in this august House. Madam, I support the Motion.

**\*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR):** I beg to lay the written speech on Motion of Thanks to President's Address.

We are participating in the debate on the Motion of Thanks to the President's Address. As President's Address is prepared by Cabinet so it is quite natural that it will reflect the achievement of the Government and also the policies and programmes of the Government.

When we are discussing of President's Address we see that as per the Human Development Index the position of our country is gradually decreasing ranking down to 128 from 126 among 177 countries. We all love our country. We are proud to be Indian. But what is shame to us is that even after 62 years of independence we have large number of illiterates in the country. Almost 17% of the World Population live in India. That is out of six people in the world one is Indian. But out of total adult illiterate people in the world almost 34% live in India. That is out of three world illiterate one is in India. The case of female illiteracy is more horrible.

More than 70% of our population live in country side. Most of them are Kisans (peasants). But what is the plight of the farmers? Almost 2 lakh farmers have committed suicide because of the anti-farmer, rather say, anti-people policies of the UPA Government taken in last six years and also of the policies taken by N.D.A. Government in the past. Nothing has been said in the President's Address about the land reform programme of the government. No new direction has been given for enhancing the irrigation facility and also supplying subsidized seeds and fertilizers to the farmers. No action has been taken for fair and remunerative price for the farmer's product.

The Government takes pride in NREGA, now named as Mahatama Gandhi NREGA. But we have failed to provide 100 days work to all families for whom the scheme is meant. What is deplorable is that corruption is taking place in implementation of the programme. The Government should come forward with plans and programme for the poor, particularly for the rural poor and the poor living in the Basti (slum dweller) in the towns. There should be no divisions as APL and BPL category because the criteria that Central Government has fixed up is so inaccurate and wrong that it keeps many really deserving poor people out of the list of BPL category. In fact, there it keeps many really deserving poor people out of the list of BPL category. In fact, there is no specific data numbering of families below poverty line. Planning Commission has one data, Arjun Sengupta Committee, Saxena Committee or Tendulkar Committee have another. What is the need of the time is to correct the Planning Commission data and enhance the percentage of BPL family.

Price hike of essential commodities has risen to an alarming position, almost reaching to 20% of food inflation rate,

what has never been in last 26 years. Government has failed to keep its promise to control the price hike. To add fire to the fuel, Government has recently increased the prices of Petroleum Products, thereby causing further rise of price hike. I strongly urge upon the Government to withdraw such hike of Petroleum products. Government should take appropriate action to make Public Distribution System universal, without making it a targeted one. In addition to that, as a measure to control price hike, Government should make ban on forward trading on all agricultural products and stop commodity exchange. Government should distribute 35 kg of foodgrains at the rate of Rs.2 per kg, to all BPL family.

Another important problem in our country is the question of unemployment. Nothing has been said about creation of new jobs. What is of more concern is the issue of job loss. More than 20 lakhs workers have lost their jobs. Even Railway and other Departments are not fulfilling their vacant posts. Government should take action of this.

Hon'ble President has referred to in her address about the threat and danger of left wing extremists. These forces are attacking and taking the lives of innocent peoples, Jawans. In my state West Bengal also in parts of three districts such thing is happening. So we all should come forward to face the challenge of left wing extremism. Government, particularly Central Government should take firm stand and strengthen joint operation. But sorry to mention that there is one political party. Who is part of the coalition government and they are supporting the so called Maoist Activities and demands for stopping joint operation. This should be checked and condemned.

Another important issue into which Hon'ble President has not mentioned anything is the issue of implementation of the Rangaraj Misra Commission recommendation. It is the crying need of the hour. The government should place the action taken report in the house West Bengal has already taken some positive step by announcing ten percent reservation for educationally, economically, backward section of the Muslim community.

The next issue is the question of bringing legislation for 33% female reservation. I strongly demand that such legislation should be tabled in this current budget session.

My last point is the issue of education. Right to Education Bill has recently been passed by making provision for 6-14 years children's free and compulsory education. But the anomalies in the Bill, now Act, be rectified. Central Government should come forward to allot more fund to the states to make it a success. While implementing this provision Union Government should keep in mind the democratic federal structure of the country. With these words, I thank to the Chair and conclude by written speech.

**\*श्री जयंत चौधरी (मथुरा):** मैं अपने दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में काफी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून का चरित्र मूलतः औपनिवेशिक है। 1894 में इंग्लैण्ड के व्यापारिक हितों को साधने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण कानून की शुरुआत की थी। आजादी के बाद उस कानून में समय-समय पर संशोधन होते रहे। किन्तु आज केन्द्र और राज्य सरकारें इस कानून का जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं उसके नतीजे ईस्ट इंडिया कम्पनी की अपेक्षा जनता के लिए अधिक भयावह रूप में सामने आ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक हितों के लिए आमतौर पर सड़क, अस्पताल, स्कूल अथवा सरकारी कार्यालय की इमारतें बनाने के लिए किया जाय। जहाँ तक किसी औद्योगिक मिल या कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रश्न है तो वहाँ पर भी उद्योगपतियों को भूमि किसानों से सीधे लेनी चाहिए। इसमें सरकार का दखल कहां तक उचित है?

आज स्थानीय आबादी जिसे अधिग्रहण के चलते भूमि से बेदखल किया जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। प्रभावित किसानों और मजदूरों को अधिग्रहीत भूमि पर लगने वाले उद्योगों में रोजगार मिलने की सम्भावना लगभग न के बराबर होती है, इसी का नतीजा है कि आज भारत में करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हुई है, कुछ गिने-चुने लोग खरबपति हुए हैं, तो ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं जिनके पास दो जून की रोटी भी नहीं है। इस तरह हमारा समाज एक असंतुलित विकास का शिकार हो रहा है। पिछले 15 वर्षों में बड़े-बड़े उद्योगों में श्रमिकों की संख्या लगातार घटी है पर उनका मुनाफा तेजी से बढ़ा है।

यहां मुझे चौधरी चरण सिंह जी के वो उद्गार याद आते हैं जो उन्होंने 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती के विरोध में व्यक्त किये थे। उन्होंने कहा था कि **किसान अपनी जमीन को माँ की तरह प्यार करता है। भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके लिए सम्मान की वस्तु होता है।** वा जान दे सकता जमीन नहीं। किसान और भूमि के बीच क्या रिश्ता है, यह हमें समझना होगा।

दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 1972 में महिपालपुर समालखा आदि गांवों की जमीनों की भूमि को अधिग्रहण किया गया था, प्रति एकड़ 5500 ₹0 का मुआवजा मिला था और आज वहीं जमीन व्यवसायियों को होटल आदि के लिए महंगे दामों पर दी जा रही है। किसानों की भूमि जब ली जाती है तो उसका मूल्य कम होता है और अधिग्रहण करने के बाद उसका मूल्य एकाएक बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? महोदया 21 जुलाई, 2009 को यमुना एक्सप्रेस-वे की अधिसूचना जारी की गयी थी। इसके अन्तर्गत 850 गांवों को अधिसूचित कर दिया गया है तथा यमुना एक्सप्रेस वे आज 90 प्रतिशत सिंचित और उपजाऊ भूमि पर बनाया जा रहा है। आज 3000

के 107452 गांवों में 5 से 6 हजार तक गांव अधिसूचित कर दिये गये हैं वो भी पिछले 2-3 वर्षों में। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कृषि भूमि 1980-81 में 185 मिलियन हेक्टेयर थी और 2005-06 में 182.57 मिलियन हेक्टेयर रह गयी है मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि अंततः रोटी सिर्फ खेती ही दे सकती है। हम इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट अनाज आयात करके नहीं भर सकते। फिर अन्न आयात करने के भी अपने खतरे हैं। हम फार्मूला वन रेस, गोल्फ तथा महंगी गाड़ियों के बिना तो रह सकते हैं, पर बिना अन्न के नहीं।

भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के सैक्शन-17 में Urgency clause का भी दुरुपयोग हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के कितने ही इंडस्ट्रियल पार्क तथा रिहायशी इलाकों के लिए कितनी ही भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है, पर बीस साल के बाद भी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जिन बड़े-बड़े उद्योगतियों को किसानों की उपजाऊ जमीनें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम पर दी जा रही हैं उनका उद्योग लगाने के कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे रोजगार का कितना सृजन हो रहा है, यह भी मानने की बात है। महोदया, सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1400 एकड़-भूमि अधिग्रहण की गयी थी और वहां पर केवल एक एलपीजी प्लांट लगा हुआ है।

आज इस बात की जरूरत है कि एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाई जाये, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाये कि किस तरह की भूमि उद्योगों तथा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की जायेगी तथा कौन सी भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखी जायेगी। आज गंगा-यमुना के मैदान में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) और एक्सप्रेस-वे के नाम पर जिस तरह खेती की उर्वर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह एक आत्मघाती कदम है। इसके दो भयावह परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं : एक तो अपनी भूमि से बेदखल होकर किसान मजदूरों के रूप में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी के आंकड़ों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण खाद्यान्न के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के नाम पर कृषि भूमि का जिसतरह अधिग्रहण किया जा रहा है उससे हमारे सामने भविष्य में खाद्यान्न का संकट पैदा होने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में भारी मात्रा में कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति और भयावह हो जायेगी। महोदया, आज भारत की महती आवश्यकता है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करें। सरकार न्यूक्लीयर लायबिलिटी एक्ट को लाने के लिए तो चिंतित है परन्तु किसानों और मजदूरों से संबंधित भूमि अधिग्रहण पर संवेदनशील नहीं है।

इस देश का किसान मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी में ही पलता बढ़ता है और समाज के अन्य तबकों का पेट भरते हुए अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है किन्तु यदि उसके शोषण का कुचक्र जारी रहता है तो वह शोषक को भी मिट्टी में मिला देता है। इसलिए भूमि अधिग्रहण की इन अन्यायपूर्ण नीतियों के नाम पर किसान का ये शोषण रुकना चाहिये अन्यथा हमें राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों को एक दिन घटित होते हुए देखना होगा-

**जब कभी अन्याय का, अपकर्ष का घट फूटता है**

**तब मनुज ले प्राण हाथों पर, दनुज पर टूटता है**

जब अन्याय और शोषण की सीमाएं टूट जाती हैं तो कमजोर मनुष्य भी अपने से कई गुना शक्तिशाली पर प्रतिरोध के लिए टूट पड़ता है।

आज की जरूरत है कि हम पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को रह करके नया कानून बनायें, जिससे कि कृषि भूमि, किसानों और मजदूरों के हितों को संरक्षण मिल सके।

**अध्यक्ष महोदया :** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Now I would request the hon. Prime Minister to reply.

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker, I rise to join all Members of this august House in conveying our sincere thanks to the hon. President of India for her enlightening Address. Over the past two days we have had a very constructive debate on the issues covered in the Rashtrapati's Address. While several Members have expressed satisfaction at the working of the Government, some others have criticized it. This is as it should be.

Madam, before I come to the main subject, I would like to make a mention of the stampede that occurred yesterday at a temple in district Pratapgarh. The issue, I believe, had been raised by the concerned Member of Parliament in the Lok Sabha yesterday. I join all hon. Members in conveying our heartfelt condolences to the families of the deceased and wish speedy recovery to normal health of those who have suffered injuries. We have decided to make from the Prime Minister's National Relief Fund an *ex gratia* payment of Rs. 2 lakh each to the next of kin of the deceased and Rs.50,000 to the seriously injured.

Madam Speaker, the essence of the hon. President's Address is contained in paragraph three, and I seek your indulgence to read that paragraph once again. It says:

"My government was voted to office with a clear cut mandate to protect and deepen the values of pluralism and secularism, and to ensure rapid growth with justice and fairness for all. Since assuming office in May 2009, my government has worked single-mindedly to build on the achievements of its earlier term to deliver the promise of faster and more inclusive growth. The *aam aadmi* was and is at the core of this promise; the *aam aadmi* had to be protected against the ravages of the worst ever global economic crisis since the Great Depression and against the failure of the monsoon in large parts of the country in mid-2009."

Madam, our economy's performance has to be judged against the twin impacts of the international financial crisis which suddenly erupted in September, 2008 and then subsequently the failure of the south west monsoon in the year 2009. I sincerely believe that the way our Government has dealt with the impacts on our economy of these two adverse turns in our circumstances beyond our control is praiseworthy and indeed the whole world is praising India for the success with which we have achieved in this country.

Under the impact of the global economic crisis, the mighty countries of America and Europe have experienced negative growth rates. In 2008-09, India's growth rate also declined but we still maintain a growth rate of 6.7 per cent. In the current year, we will have a growth rate of minimum of 7.2 per cent but possibly going up to 7.5 per cent.

In the fiscal year 2009-10, the growth rate of the economy will be probably close to, what I have mentioned, 7.5 per cent but the most conservative estimate is seven per cent. In the next fiscal year, we are confident of achieving a growth rate of eight per cent or more; and the year thereafter we will be able to return the economy to nine per cent growth rate.

Why do I emphasise the growth rate? Madam, growth is not an end in itself. The end is the well-being of our people. Growth is only a means to provide relief to those who are suffering; growth is a means to find resources to spend on education, on health, on rural development, on social security. If we do not grow fast enough, we may talk about removal of poverty, we may talk about expanding irrigation and other facilities in rural India but these will all remain pipe dreams. The fact that the first three years of our Government saw a sharp increase in the growth rate, enabled our Government to devote a lot more resources for rural development, for agricultural development, for education.

Therefore, it is very important that the economy should get back to the growth rate of nine per cent or more. I am confident that the macroeconomic fundamentals of our economy are very sound. Why do I say this? Ten years ago, nobody would have imagined that India's savings and investment rates, can be as high as 35 per cent or 36 per cent. In the last four to five years, we have so managed the economy that both the savings and investments in our country now are equal to the savings and investment rates which prevailed until 10 years ago only in the countries of South East Asia or East Asia.

Moreover, I feel, in the years to come, in the next two decades, the dividend arising from the sharp rise in the working age population to total population of our country will provide another positive factor to push the savings rate of this country close to 40 per cent of our national income. If we manage our economy well, if we manage the creation of social and physical infrastructure well, if the processes of governance are improved to reduce the scope for corruption, I think, there is no barrier to India entering on a long-term basis the age of double digit growth. This is the vision that our Government is working to realise.

I recognise that there are current problems, which cannot be wished away. The hon. Members from both sides of the House have referred to the price situation. I will be the last one to say that the behaviour of food prices in the last one year is something which does not worry us. We have been worried about it a great deal and to the extent that we could adopt measures, we have adopted; and the House has my assurance that if any practical methods can further bring relief to our people, our Government will always be sensitive to the concerns of the *aam aadmi*...(Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अब तक क्यों नहीं हुआ?...(व्यवधान) क्यों डीजल के दाम बढ़ाये?...(व्यवधान)

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, the crisis situation that emerged was a byproduct of events over which we had no

control. There is, first, the effect of international commodity prices which have gone up and since India is no longer a closed economy, despite what Dr. Joshi may say, we are dependent on imports of substantial quantities of vegetable oils. In years of shortage, we depend upon import of sugar. We are dependent to a substantial extent on import of pulses. When international prices of these commodities rise, I think, there is inevitably an impact in our country.

When international prices of rice and wheat go, if we do not pay remunerative prices to our farmers, our ability to procure for the Public Distribution System may be seriously in danger, and, therefore, we have to pay remunerative prices to our farmers but the side effect of that is, it raises the floor price or market determined prices.

I invite the House to reflect on a situation that we were faced with. There was the global recession. Simultaneously, because of the drought and because of the high commodity prices world wide, there was pressure on prices. We could have dealt with the price effect by a very tough monetary and fiscal policy which would have depressed the demand. Would that have been the course which the House would recommend to me? If we had gone that route, there would have been large scale unemployment and steep fall in industrial production in our country. At a time when the world is faced with a global economic crisis and declining rates of employment, we have so managed our economy that we have not allowed, I think, large scale unemployment to emerge as a problem in our country, despite the world wide recession that prevails.

At the same time we were able to introduce a large number of stimulus packages which ensured that the interests of the weaker sections of the society were protected. Take for example, the National Rural Employment Guarantee Scheme. Madam, 4.5 crores of households have benefited. Fifty per cent of them are women. Fifty per cent of them are Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am not saying that in one go or in one short period of five years, we can remove poverty. But if we are sincere, if we use all the resources of the economy to step up our growth rate, if we manage our fiscal situation well, we can certainly soften the harsh edges of extreme poverty in a period of about five more years.

We need to invest more in education. We need to invest more in health. We are doing that. We need to invest more in rural infrastructure and urban infrastructure. We are doing that. But more needs to be done. Please help us to strengthen the growth impulses in our economy so that we can accelerate the tempo of social and economic change.

I have said growth is important not in itself, but because it provides us the resources to tackle the problems of poverty, ignorance and disease about which Jawaharlal Nehru spoke from the Central Hall of Parliament on the midnight of August 14, 1947.

Madam, many Members have in the discussion expressed their anxiety about rising prices. We had a separate discussion on this issue. But I would again like to inform this House that the Government has been alive to the problem and has taken all possible measures to address the issue. To put matters in perspective, it is important to recognise that in 2009 we had one of the most severe droughts in recent history, the worst since 1972. As a result, the production of food grains, pulses and oilseeds has been adversely affected. Production of sugarcane has also gone down. This was preceded by the economic slow down. To respond to this, the Government had to stimulate demand and increase the availability of bank credit.

We have taken decisive action on several fronts. We acted early to limit the fall in the Kharif production. As a result, we could contain the reduction in food grain production to a large extent. We have been able to procure around 23 million tonnes of rice this year which is not very different from what we had procured last year during the same time. There should be no panic on the food situation front considering the comfortable level of food stocks that are available with the Central Government. Rabi prospects are also very encouraging. Post-monsoon rains have been good. All this augurs well for our ability to stabilise food prices at a reasonable level. We have permitted import of raw and white sugar at zero duty and imports are taking place. Enforcement in terms of imposing stock and time limits is the hands of State Governments. We have empowered State Governments to do so through the Essential Commodities Act and I have requested the Chief Ministers to take stern action against hoarders.

Madam Speaker, many hon. Members have spoken about the export of sugar. Very often we have to honour prior international commitments. The amount of sugar that India has exported relative imports is so small that it is surprising that so much is being made out of this. In November 2009, India exported sugar worth Rs.7.94 crore whereas it imported sugar worth Rs.611.40 crore. In December 2009 the exports of sugar were worth Rs.12.34 crore whereas the imports were worth Rs.216.90 crore. From this, it will be obvious that the factors responsible for a sharp increase in sugar prices are to be found in the cyclical nature of production of sugarcane. There is a cycle which has been noticed for almost 50 years in the behaviour of sugarcane production. For two or three years in one cycle there is upward pressure on prices followed by a steep fall in prices.

**13.00 hrs.**

We have to find ways and means to stabilise the sugar economy despite this behaviour and we will explore ways and means to see that in future prices of sugar can be stabilised at reasonable levels unmindful of the cyclical nature of the production of sugar.

Madam, I now come to the internal security issues. The overall security situation in our country has remained satisfactory in the last year. This is not to ignore the horrible terrorist act in Pune. But taking an overall view of the internal security situation, what I am stating, I think, is what is the reality. A number of concrete steps have been taken to strengthen and reorient our security architecture in order to meet the growing threats of terrorism, insurgency and communalism. We have remained in close touch with State Governments to evolve a common and practical approach. We are taking firm action to curb naxalite violence. It is unfortunate that they are targeting innocent people and destroying roads, power lines and other essential infrastructure. In some places we have received reports of the use of children; we have drawn up an integrated plan to tackle the problem in consultation with the States. A high-level meeting was recently held with all the Chief Ministers where we reviewed the situation. The security forces have achieved several notable successes. While we are determined to take firm action, we are ready to talk to any group that abjures violence unconditionally and agrees to abide by the due constitutional process.

Madam, the National Investigation Agency has commenced its work. Four regional hubs of National Security Guard have been set up. We are in the process of setting up a National Counter-Terrorism Centre. A National Committee on Coastal Security has been set up which has adopted an integrated approach to coastal security and has taken major initiatives and decisions for registration of vessels, issue of identity cards to fishermen, installation of transponders on boats and setting up of four Joint Operation Centres. Coastal police stations and interceptor boats have become operational under the Coastal Security Scheme.

To supplement the efforts of the State Government in modernising their police force, we have provided Rs. 1,250 crore during the current year of which Rs. 955.53 crore have been released to States up to 28<sup>th</sup> January this year. This has helped States to augmenting the resources available to police forces in terms of vehicles, weaponry, communications, training, forensic facilities, intelligence capabilities, security equipment and buildings. The Bureau of Police Research and Development is engaged in impact assessment study of the scheme so that the scheme could be improved.

Some hon. Members have said that agriculture has been growing at negative rates. This is indeed surprising. A drought is beyond anybody's control. A severe drought does result in negative growth in agriculture and it is no surprise that agriculture is expected to grow at minus two per cent in 2009-2010.

But we should not forget that in 2002-03, following the drought of 2002, agricultural growth went down by a good seven per cent. Food production went down from 202 million tonnes in 1998-99 to 174 million tonnes in 2002-03. I would also like to remind Members that the agricultural sector has been growing at an average rate of four per cent during the period 2005-2008 compared to the growth rate of around two per cent from 1997 to 2002. Our pro-farmer policies have borne fruit.

For the first time in the recent past, we have reversed the trend of declining investment in agriculture and stepped up investment in agriculture through the Accelerated Irrigation Benefit Programme, the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the National Food Security Mission, the National Horticulture Mission and other such schemes. We should also not forget the investment in water conservation structures that is being made through millions of works under the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme. Food production has increased from 174 million tonnes in 2002-03 to 233 million tonnes in 2008-09, which represents a growth rate of around six per cent per year. We are, however, conscious that a lot more needs to be done to improve agricultural productivity and we are committed to continuing our efforts to increase both public and private investment in agriculture and diversify our agriculture so that higher farm incomes provide stability to the lives of our farmers.

Dr. Joshi referred to our going to America to seek solutions to agricultural problems of our country. I wish to assure him that there is no scope for this sort of *galatfahmi*. I think, our Government recognises the imperative of food security and that self-sufficiency in basic food grains has to be a part of the National policy for development. This is a policy which we have pursued under successive Congress Governments way back from the sixties till date. We will continue to pursue it hereafter as well.

Madam, the decision to pay remunerative prices by way of minimum support prices is a part of our effort to incentivise growth of agricultural production and productivity.

I think, Advaniji raised the issue of farmers' suicide. Our Government has been very sensitive to the issue of farmers'

suicide and everything possible in terms of Government action is being done to ameliorate agrarian distress. The loans of small and marginal farmers have been waived and for other farmers, a one time settlement has been made. These measures have benefited 3.68 crore farmers to the extent of Rs. 70,000 crore. A special package for suicide-prone districts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala has been implemented. The minimum support prices of most agricultural commodities have been enhanced substantially over the last six years. It was ensured that fertiliser prices did not increase during the same period. We have, in fact, reduced the prices of complex fertilisers in 2008 in order to rationalise nutrient use.

The increase in the Minimum Support Price of cotton has come as a great boon for cotton production in Vidharba and other cotton-growing regions of the country.

It has been said that the loan-waiver scheme has not helped farmers and it has only helped banks. â€ (Interruptions) Nothing can be farther from the truth. It is surprising that we forget that nearly Rs. 70,000 crore, that was recoverable from farmers, has not been recovered. It should also be borne in mind that owing to defaults in repayment, farmers would not be eligible for fresh credits. We have ensured the flow of fresh credit to the farm sector. During 2008-2009, against a target of Rs. 2,80,000 crore, the total credit flow to agriculture was Rs. 3,01,582 crore. During this year, we have a target of disbursing Rs. 3,25,000 crore and so far Rs. 2,18,202 crore have already gone to the agricultural sector.

We have accorded very high priority to the welfare of minorities. We have accepted most of the recommendations of the Sachar Committee and this House has been informed of the action taken on them. We have launched special programmes aimed at social, economic and educational development of minorities. Three new scholarship schemes have been started and are under implementation. We expect more than 40 lakh students to benefit from this scheme in the Eleventh Plan. At least 30 per cent of these students would be girls.

Madam, the new 15- Point Programme aims to ensure that at least 15 per cent of benefits in certain schemes flow to minorities, and the schemes for minority welfare are being closely monitored. Under this programme, additional school rooms; drinking water supply schemes; Anganwadi centres; and houses are being constructed for the minorities.

To improve the access of minorities to bank credit, we have set the target that at least 15 per cent of the priority sector lending will flow to them. During 2008-2009, more than Rs. 82,000 crore of bank credit, under priority sector lending, went to the minorities. This represents nearly 12 per cent of the total priority sector lending. We hope to improve on this in years to come.

Minorities have not been represented adequately in Government services. We have taken steps to correct this situation, and as a result the share of minorities in Government jobs has increased over the past three years.

Madam, some Members have raised the issue of rights of tribals over forests. We are making genuine efforts together with the State Governments to ensure early disposal of claims and distribution of titles under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. I have also requested the Chief Ministers of concerned States on three occasions to take all measures necessary to accelerate the process of implementation of the Act and to ensure expeditious distribution of title deeds to all eligible claimants. This was reiterated during the Conference of Chief Ministers and State Ministers held in November 2009 to review the implementation of the Act. The Ministry of Tribal Affairs is closely monitoring the progress in this regard.

Madam, some Members have expressed concern over the implementation of the National Rural Employment Guarantee Scheme. Let me say that this is a scheme, which has the potential to change the face of rural India. To improve its impact, we have initiated measures to bring in greater transparency and accountability. ... (Interruptions)

**श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** मान्यवर, जब सबका बढ़ा रहे हैं तो सांसद निधि भी बढ़ा दीजिए... (व्यवधान)

**DR. MANMOHAN SINGH:** An ombudsman scheme for setting up an independent grievance redressal mechanism at the district level has been formulated, and States are in the process of setting up district ombudsmen. Social Audits by *Gram Sabhas* have also been taken up. Details of job cards, muster rolls and works undertaken have also been placed in the public domain. A scheme for independent monitoring by eminent citizens has been formulated. Efforts will be made to continue to improve the implementation of this revolutionary scheme.

Madam, Advani Ji had raised the issue of black-money deposited in foreign countries. The Finance Minister had written to Shri Advani Ji in May, 2009, providing information about the action taken. Subsequently, we have moved further in the matter. Twenty countries and jurisdictions have been prioritized for entering into agreements regarding exchange of information and assistance in collection of taxes. Negotiations have been completed with the Bahamas and Bermuda, and

steps are being taken for signing of agreements.

We have also approached Switzerland for renegotiation of our tax treaty, so that we can have access to bank information. Negotiations were held in November, 2009, and the matter is being pursued for finalising a new protocol, through which we will be able to obtain information in specific cases. India is an active participant in global fora for improving transparency and exchange of information on tax matters.

Hon. Advani Ji had also raised the issue of 'One Rank, One Pension' to Ex-Servicemen. He has stated that the commitment I made in my last year's Independence Day speech and Finance Minister's promise in his Budget Speech of July 6, 2009, have not been honoured. This is not correct. The factual position is that we had constituted a Committee under the Cabinet Secretary to look into the issue of 'One Rank, One Pension' and other related matters. The Committee did not recommend 'One Rank, One pension'. But whatever recommendations the Committee made to substantially enhance the pensionary benefits of personnel below officer rank and commissioned officers were accepted by the Government, and this is what I had stated in my Independence Day's speech. The recommendations which have been accepted cover what the Finance Minister had promised in his Budget Speech of 2009. Of the seven recommendations that the Committee made, five have been implemented. The two recommendations which have not been implemented will be implemented very soon.

Madam, I share the concern of hon. Members about the need for electoral reforms. I do not think there is any dispute regarding the need for electoral reforms. Unfortunately, we do not have the same degree of unanimity on the manner in which to go about it. It has been our accepted position and also the accepted position of previous Governments that electoral reforms should be brought about only by broad-based political consensus. The recommendations of the Election Commission regarding electoral reforms and other proposals received by us are presently under consideration of the Standing Committee of Parliament. Therefore, the Committee would be able to recommend measures which should find support in this House across the political spectrum.

We introduced the Women's Reservation Bill in the Rajya Sabha in May 2008. We have already considered the Report of the Standing Committee of Parliament on this Bill. It will be our endeavour to bring the Bill before Parliament in this very session. I sincerely hope that hon. Members would support the Bill as it would be the strongest affirmation of our commitment to the empowerment of women.

I should say a few words about foreign policy. The Government's foreign policy has been based on national consensus and full adherence to the principles and objectives laid down by the founding fathers of our Constitution. The foreign policy that we have pursued in the first term of our Government and on which we have built upon in the second term has yielded solid dividends. India's standing in the comity of nations has never been higher. In the troubled world that we live in, there is respect for India's role as a force of moderation, reason and stability. The resilience of our democracy, our commitment to pluralism and secularism and the strength of our economy have enhanced our standing in the world.â€ (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please maintain order.

DR. MANMOHAN SINGH: The situation in our neighbourhood is a matter of high priority for us. We have had very intense and substantive interactions with our neighbours in the last nine months. Several Members have voiced their concerns over the situation in Pakistan and the terrorism that is emanating from there against India. The Government fully shares these concerns. We are taking all necessary steps to strengthen our internal security and defence capabilities.

Government has kept Parliament fully informed at every stage of our policy towards Pakistan. I had made a detailed statement on our approach towards Pakistan in this august House on 29<sup>th</sup> July, 2009. The External Affairs Minister briefed the House on the last round of Foreign Secretary level talks in February. Our policy towards Pakistan is consistent, cautious and realistic.

I have never believed that the channels of communication with Pakistan should break down. Even at the height of the cold war, the Americans and the Soviets used to speak to each other. The chances of miscalculation can only increase in an environment of no contact. I therefore, personally conveyed our concerns to President Zardari when I met him in Russia and later to Prime Minister Gilani at the NAM Summit last year. I had made an offer of talks on humanitarian and other issues in October last year during my visit to Anantnag. The decision to resume talks at the Foreign Secretary level is not a sudden decision but a calculated one based on weighing all the costs and benefits. The fact of the matter is that the rest of the international community is talking to Pakistan. So, our not talking to them is not going to isolate them. We have made our point strongly, but we cannot wish away the problem by not talking to them. Dialogue is the only way forward for civilized countries to resolve their problems. But it is equally true that for any meaningful dialogue to proceed, the terror machine has to be controlled by Pakistan even if non-state actors are at work. I have said so in Parliament a number of



times and that remains our consistent position. We have left Pakistan in no doubt about our concerns and our expectations with regard to the actions Pakistan must take against the terrorist groups operating on Pakistani soil and targeting India. Pakistan must fulfil its assurances that it will not permit any territory under its control to be used to support terrorism in any manner.

Madam, some hon. Members have referred to my discussions in Saudi Arabia on Pakistan. Saudi Arabia is also affected by terrorism and this was one of the subjects that came up in our discussions. I discussed India-Pakistan ties in this context. I mentioned to the Saudi leadership, as I have to other world leaders as well, that all problems between India and Pakistan can be resolved through meaningful bilateral dialogue, if only Pakistan could be urged to take a reasonable attitude in dealing with those terrorist elements who target our country. I wish to reaffirm that no offer was made seeking mediation. We do not need any mediation. We are talking directly to Pakistan.

Advaniji said that we acted under US pressure.

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€/\**

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, I think we do a disservice to any Government and Prime Minister of this proud country, if we say that such fundamental matters of national security and foreign policy are based on anything but our supreme national interest.

I have had many discussions with President Obama since he took office. I categorically state that not once has he sought to pressurize India into taking one position or the other. On the contrary, he has always expressed understanding of the positions we have taken from time to time. I would urge the Opposition not to spread disinformation on sensitive aspects of our foreign policy.

Let me say, Madam, that we do not wish to see the involvement of foreign powers in South Asia. Whatever our problems, we must learn to talk to each other and to solve our problems in a peaceful manner using our own creative genius.

Madam, in Afghanistan our assistance has received widespread support among the people of Afghanistan. The entire nation was outraged by the most recent brutal attack in Kabul on February 26, which has led to the loss of seven innocent Indian lives. These Indian nationals were in Afghanistan on a mission of goodwill and friendship helping to construct the peaceful and democratic Afghanistan that our Afghan friends desire. We condemn this cowardly act. I wish to assure this House that such attacks will not bend the will of the people of India.

President Karzai had telephoned me and I have requested him to ensure the safety of all Indians. I assured him of any support and assistance that may be required. We are closely monitoring the developments with regard to Afghanistan and we will assist the people of Afghanistan in securing their legitimate right to determine their destiny in the manner they choose without outside interference.

Madam, Joshi ji made some comments about India-China relations. Let me say, China is our important neighbour, with whom we have a comprehensive and multi-sectoral relationship. We wish to build upon the achievements so far so as to create a partnership that is mutually beneficial. We are convinced that good relations with China are in the interests of both countries, and will contribute to peace, security and stability not only of the Asia-Pacific region but also of the world. We are both committed at the highest level to maintain peace and tranquility on the border, pending the resolution of the border question. This is a complex matter which will take time to resolve. I had an excellent interaction with Prime Minister, Wen Jiabao in Copenhagen, and our cooperation in the area of climate change is a shining example how our two countries can work together on issues of global importance and those which impinge on the future of our two peoples.

In Sri Lanka, the conclusion of military operations against the LTTE has opened opportunities for finding such a lasting political settlement which will be acceptable to all communities, particularly the Tamils, within a united Sri Lanka. We have and we will continue to contribute to the humanitarian and rehabilitation efforts of the Sri Lankan Government, and to the long-term reconstruction of areas that have been affected by the military conflict. Our assistance package of Rs.500 crore for immediate relief, resettlement and reconstruction is under implementation.

We have taken several steps to diversify and broad-base our relations with Bangladesh. A major milestone in this respect was the visit of Prime Minister, Sheikh Hasina to India in January 2010. During that visit we put in place a comprehensive framework of cooperation for development of our relations, which includes a renewed commitment by both sides to actively cooperate on security issues. We have provided a line of credit of one billion US dollars for a range of

projects in Bangladesh which we intend to follow up vigorously. The Government of Bangladesh has reassured us that they will not allow their territory to be used for activities inimical to India. We have welcomed some of the steps they have recently taken in this direction.

Our country is passing through a difficult time. Security and stability are the need of the hour. Political parties can differ on various issues but I do believe it is important for us to face challenges in a united manner. I seek the cooperation and support of all sections of this House. Let us not allow narrow partisan considerations to come in the way of effective governance of this great country.

The people of India expect both the Treasury and Opposition benches to engage constructively and ensure safety, security and prosperity for our citizens. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) €/\**

MADAM SPEAKER: A number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I want to put four of my amendments No.895, 901, 912 and 928 to the vote of the House separately.

They are:

"That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about tackling global economic recession affecting Indian industries and loss of jobs of lakhs of workers and employees." (895)

"That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about streamlining the Public Distribution System in the country." (901)

"That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about steps to prevent cases of suicides by the farmers during the last few years in 'rural India'." (912)

"That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about taking any concrete steps to ensure availability of food at affordable prices to 'AAM AADMI', a large percentage of which is actually living below poverty." (928)

*...(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, will you kindly repeat the number of your amendments?

*...(Interruptions)*

SHRI BASU DEB ACHARIA : Serial numbers 895, 901, 912 and 928. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 895 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 901 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 912 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 928 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

MADAM SPEAKER: I shall now put all the other amendments together which have been moved, to the vote of the House.

*All the amendments were put and negatived.*

MADAM SPEAKER: I shall now put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 2010'."

*The motion was adopted.*

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.40 p.m.

**13.35 hrs.**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forty Mminutes**

*past Fourteen of the Clock.*

---

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forty Five Minutes past*

*Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)